

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून दिनांक : २९ मार्च 2013

विषय:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखरी(चमोली) के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-321/ XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखरी(चमोली) के भवन निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रू0. 330.00लाख के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0. 245.00लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु उक्त संस्थान हेतु अवशेष रू0. 85.00लाख (रूपया पिचासी लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।
- 2- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 4- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- 6- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

- 7- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
- 8- उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्ज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 10- आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओडशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 80-सामान्य- आयोजनागत- 001-निदेशन तथा प्रशासन-07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण- 00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, चमोली
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली/हल्द्वानी।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखरी(चमोली)।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० श्रीनगर-1(अ), चमोली।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस०एस०टोलिया)
अनुसचिव।